संविधान निर्माताओं के यादगार उद्धरण

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी: एक देशभक्त और दूरदर्शी नेता

6 जुलाई 1901 को कलकत्ता में जन्मे डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी थे – वे देशभक्त, शिक्षाविद्, सांसद, राजनेता और मानवतावादी व्यक्तित्व थे। उन्हें अपने पिता सर आशुतोष मुखर्जी, जो कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित कुलपति और कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, से विद्वता और राष्ट्रवाद की भावना विरासत में मिली। इससे उनमें भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रति गहरा सम्मान और आधुनिक वैज्ञानिक विचारों में गहरी रुचि पैदा हुई। डॉ. मुखर्जी की शैक्षणिक प्रतिभा कम उम्र से ही दिखने लगी थी। प्रेसीडेंसी कॉलेज में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के बाद, उन्होंने डी.लिट और एल.एल.डी. सहित कानून और साहित्य में डिग्री हासिल की।

इंग्लैंड में रहते हुए, डॉ. श्यामा प्रसाद ने ब्रिटिश साम्राज्य के विश्वविद्यालयों के सम्मेलन में कलकत्ता विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया और खुद को एक प्रमुख भारतीय शिक्षाविद् के रूप में स्थापित किया। 1924 में विश्वविद्यालय सीनेट और सिंडिकेट के लिए चुने जाने के बाद, वह शुरू में कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में बंगाल विधान परिषद में शामिल हुए। हालाँकि जब 1930 में कांग्रेस ने विधानमंडलों का बहिष्कार किया, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन जल्द ही विश्वविद्यालय के हितों की रक्षा के लिए एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में फिर से शामिल हुए।

कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे कम उम्र के कुलपति (1934) के रूप में उनके कार्यकाल ने उन्हें शिक्षा के लिए अपनी प्रगतिशील दृष्टि को लागू करने की अनुमति दी। उन्होंने भारतीय भाषाओं और बौद्धिक विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने छात्रों को प्रेरित करने के लिए रवींद्रनाथ टैगोर जैसे दिग्गज व्यक्तित्व को आमंत्रित किया। बाद में वे हिंदू महासभा में शामिल हो गए और 1937 में फ़ज़ल-उल-हक के नेतृत्व में एक प्रगतिशील गठबंधन सरकार बनाने के लिए गैर-कांग्रेसी ताकतों को एकजुट किया, जिसमें वे खुद वित्त मंत्री थे। वर्ष 1940 में वह हिंदू महासभा के कार्यकारी अध्यक्ष बने और भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता को अपना राजनैतिक लक्ष्य घोषित किया। श्यामा प्रसाद ने प्रशासन में राज्यपाल के हस्तक्षेप के विरोध में और प्रांतीय स्वायत्तता को अप्रभावी बताते हुए नवंबर 1942 में बंगाल मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। 1943 के बंगाल अकाल के दौरान राहत कार्यों सहित उनके मानवीय प्रयासों ने समाज की सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को उजागर किया।

स्वतंत्रता के बाद, डॉ. मुखर्जी, जवाहरलाल नेहरू के अधीन अंतरिम सरकार में उद्योग और आपूर्ति मंत्री के रूप में शामिल हुए, जहां उन्होंने चित्तरंजन लोकोमोटिव फैक्ट्री, सिंद्री फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन और हिंदुस्तान जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों की स्थापना करके भारत के औद्योगिक विकास

की नींव रखी। हालाँकि, वैचारिक मतभेदों के कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने राष्ट्रवादी आदर्शों की वकालत करने के लिए अखिल भारतीय जनसंघ (1951) की स्थापना की।

एक सांसद के रूप में, डॉ. मुखर्जी एक प्रखर वक्ता और एक सम्मानित विपक्षी नेता थे, जिन्होंने कश्मीर मुद्दे, पाकिस्तान और भारत के बीच प्रवासन, भारत की विदेश नीति, निवारक हिरासत और चुनावी सुधार आदि जैसे मुद्दों पर अपनी तीखी बहस के लिए "संसद के शेर" की उपाधि अर्जित की। भारतीय एकता के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का उदाहरण जम्मू और कश्मीर के एकीकरण के लिए उनकी लड़ाई थी। उनकी घोषणा, "मैं आपको भारतीय संविधान दिलाऊंगा या इसके लिए अपनी जान दे दूंगा," उनके समर्पण का प्रतीक था। दुखद बात है कि 1953 में कश्मीर में हिरासत के दौरान उनकी मृत्यु हो गई और इस क्षति पर सभी राजनीतिक दलों में शोक मनाया गया। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत के प्रति देशभक्ति और निस्वार्थ सेवा के एक स्थायी प्रतीक बने हुए हैं, उन्हें उनके दूरदर्शी नेतृत्व और राष्ट्रीय एकता के प्रति अटूट समर्पण के लिए याद किया जाता है।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा संविधान सभा में दिये गये भाषणों के अंश

संविधान निर्माण पर

"मेरा मानना है कि हमारे देश के उतार-चढ़ाव भरे इतिहास के दौरान, हमने अक्सर अपनी मातृभूमि के लिए एक स्वतंत्र संप्रभु राज्य की हमारी मांगों को मूर्त रूप देते हुए विभिन्न राजनीतिक दलों और मंचों से संकल्प और प्रस्ताव पारित किए हैं। लेकिन जहां तक आज के संकल्पों की बात है, तो इसका गहरा और विशेष महत्व है। यह हमारे देश के इतिहास में पहली बार है, कि ब्रिटिश शासन के अधीन आने के बाद आज हम अपना स्वयं का संविधान बनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह एक बड़ी ज़िम्मेदारी है- और असल में, जैसा कि प्रस्ताव के माननीय प्रस्तावक ने हमें याद दिलाया, यह एक गंभीर और पवित्र विश्वास है, जिसे हम भारतीय निभाने के लिए सहमत हुए हैं और हम अपनी सर्वोत्तम क्षमता से ऐसा करने का प्रस्ताव करते हैं।"

हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने पर

"यदि कोई यह दावा करता है कि भारत के संविधान में एक अनुच्छेद पारित करके, दबाव की प्रक्रिया से, एक भाषा को सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाएगा, तो मैं कहता हूं कि इसे हासिल करना संभव नहीं होगा।"

"हम हिंदी को क्यों स्वीकार करते हैं? ऐसा नहीं है कि यह आवश्यक रूप से सर्वश्रेष्ठ भारतीय भाषा है। इसका मुख्य कारण यह है कि यही वह भाषा है, जिसे आज इस देश में बहुमत से लोग समझते हैं।"

"आपको कुछ पंद्रह साल का समय मिला है, जिसके भीतर अंग्रेजी को बदलना होगा। इसका विकल्प कैसे बनाया जाए? इसे प्रगतिशीलता के साथ बदलना होगा। हमें यथार्थवादी ढंग से फैसला लेना होगा कि क्या कुछ विशेष उद्देश्यों के लिए भारत में अभी भी अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाना चाहिए।"

विदेश नीति पर

"हम शांति चाहते हैं। हम युद्ध से बचना चाहते हैं। हम बातचीत की नीति पर चलना चाहेंगे। हम धैर्यवान रहना चाहेंगे, हालाँकि जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा, हमेशा ही बहुत धैर्यवान नहीं। साथ ही हमें भटकाव की नीति का पालन करने से खुद को बचाना चाहिए। हमें निर्णय लेने में सक्षम होना चाहिए- हमें उम्मीद है कि सही समय पर सही निर्णय लिया जाएगा।"

"हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, संघ और धर्म की स्वतंत्रता के साथ हैं और हमारा संविधान लोकतंत्र के ठोस सिद्धांतों पर आधारित है। इसलिए, भारत सर्वाधिकारवाद या तानाशाही से जुड़े किसी भी सिद्धांत को स्वीकार नहीं करेगा और न ही कर सकता है।"

"जिस चीज़ की ज़रुरत है, वो है दृढ़ता। जरूरत है एक निर्णायक नीति की। आवश्यकता है अपनी मातृभूमि के हित की स्पष्ट व्याख्या की। और इन सभी को ध्यान में रखते हुए, यदि हम कार्य करना जारी रखते हैं, तो मुझे यकीन है कि हमने अब तक जो हासिल किया है, उससे कहीं अधिक करना हमारे लिए संभव होगा।"

भाषाई राज्यों पर

"यद्यपि हम इतिहास से सबक ले सकते हैं, हमें देश के विभिन्न हिस्सों में उत्पन्न हुई गंभीर स्थिति पर विचार करना होगा और हमेशा के लिए तय करना होगा कि क्या भारत मुख्य रूप से भाषाई आधार पर विभाजित होने जा रहा है। अगर मैं अपना मत रखूं, तो मैंने हमेशा यह कहा है कि भाषाई विचार ही एकमात्र ऐसा विचार नहीं हो सकता, जिसके आधार पर भारत को विभाजित किया जा सके। आपको प्रशासनिक दक्षता, सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि और देश की एकता जैसे अन्य कारकों को भी ध्यान में रखना चाहिए। ये महत्वपूर्ण कारक हैं, जिन्हें कोई भी समझदार व्यक्ति अनदेखा नहीं कर सकता है।"

स्वैच्छिक दान पर

"अब हमें प्रति दिन 40 रुपये मिलते हैं। मुझे नहीं पता कि इसके बाद लोक सभा के सदस्यों का भत्ता कितना होगा। आइए हम प्रति दिन 10 रुपये की स्वैच्छिक कटौती पर सहमत हों और इसे अलग कर दें ताकि इस राशि को वे घर खोलने में प्रयोग किया जा सके, जहां महिलाओं और बच्चों (अकाल प्रभावित क्षेत्रों की) को रखा जा सकता है और खिलाया जा सकता है।"